BARC IN ACTION MODE WITH RLD

BARC ushers more transparency in the television news business.

Broadcast Audience Research Council (BARC) is getting into action mode with the Govt's directive to share Respondent Level Data. What will be the impact of RLD on TV channels, remains to be seen.

The Ministry of Information and Broadcasting has granted Broadcast Audience Research Council (BARC) India permission to share Respondent Level Data (RLD) with broadcasters, some news channels said they are still waiting for the TV ratings body to share more details on the procedure, guidelines and the cost.

Broadcasters are sceptical on how the data will affect the news business. Some have welcomed the step. Channels can use RLD to determine which market and town to target, as well as how people consume news from the channel.

A section of the news players feel there will be no major impact from an external perspective and may help better content planning,

I&B Secretary Apurva Chandra, gave his consent to BARC India officials to share with broadcasters Respondent Level Data, which it is already sharing with advertisers and agencies.

Raw Level Data is the information gathered from households by people meters and is unprocessed data and Respondent Level Data is the result of applying outlier management tools and algorithms to the raw data. In simpler terms, it can be described as the ultimate data that is recognized as TRPs (Television Rating Points).

BARC charges the agencies Rs 60 lakhs per annum for the Respondent Level Data will be made available to the broadcasters. BARC may charge less for the Respondent Level Data to broadcasters. ■

आरएलडी के साथ एक्सन मोड में बीएआरसी

बीएआरसी, टेलीविजन समाचार व्यवसाय में और अधिक पारदर्शिता लाना चाहता है।

ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) प्रतिवादी स्तर पर डेटा साझा करने के सरकार के निर्देश कए साथ एक्सन मोड में आ रहा है। आरएलडी का टीवी चैनलों पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) इंडिया को प्रतिवादी स्तर डेटा (आरएलडी) साझा करने की अनुमति दे दी है। कुछ समाचार चैनलों ने कहा है कि वे अभी भी प्रक्रिया दिशा निर्देशों और लागत पर पर अधिक विवरण साझा करने के लिए टीवी रेटिंग निकाय का इंतजार कर रहे हैं।

BROADCAST AUDIENCE RESEARCH COUNCIL INDIA

प्रसारक इस बात को लेकर संशय में हैं कि डेटा समाचार व्यवसाय को कैसे प्रभावित करेगा। कुछ लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है। चैनल आरएलडी का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि किस बाजार और कस्बे को लक्ष्ति किया जाये, और साथ ही लोग चैनल से समाचारों का उपभोग कैसे करते हैं।

समाचार खिलाड़ियों के एक वर्ग का मानना है कि बाहरी दृष्टिकोण से कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे बेहतर सामग्री योजना बनाने में मदद मिल सकती है।

आईएंडबी सचिव अपूर्व चंद्रा ने बीएआरसी इंडिया के अधिकारियों को प्रसारकों के प्रतिवादी स्तर के डेटा को साझा करने के लिए अपनी सहमति दी है, जिसे वे पहले से ही विज्ञापनदाताओं और एजेंसियों के साथ साझा कर रहा है।

रॉ स्तर के डेटा लोगों के घरों में मीटर द्वारा एकत्र की गयी जानकारी है और यह असंसाधित डेटा है और प्रतिवादी लेवल डेटा कच्चे डेटा पर बाहरी प्रबंधन उपकरण और एल्गोरिदम लागू करने का परिणाम है। सरल शब्दों में, इसे अंतिम डेटा के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसे टीआरपी (टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स) के रूप में पहचाना जाता है।

प्रतिवादीस्तर के डेटा को प्रसारकों को उपलब्ध कराने के लिए बीएआरसी एजेंसियों से प्रति वर्ष 60 लाख रुपये का शुल्क लेता है। बीएआरसी प्रसारकों से प्रतिवादी स्तर के डेटा के लिए कम शुल्क ले सकता है। ■